(ख) इस प्रकार से बद हो जाने के कारण हुई किसी हानि की कोई सूचना नही मिली है । बिजली की कम सप्लाई होने के कारण हुई हानियो का मूल्याकन करना कठिन है क्योकि बिजली की कम सप्लाई के अलावा अन्य अनेक बातें ऐसी होती है जिन का प्रभाव औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन पर पडता है ।

(ग) और (घ) 1983–84 तक की अवधि के लिए बनाए गए विद्युत् कार्यक्रम में बिहार राज्य की कई निर्माणाधीन और हाल मे स्वीकृत की गई परियोजनाएं शामिल है । इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन से तथा उपलब्ध क्षमता के इष्टतम समुपयोजन से राज्य मे बिजली सप्लाई की स्थिति काफी सुधर जाएगी और सभावित माग इस से पर्याप्त रूप से पूरी हो जाएगी । विद्युत् आयोजन एक सतत प्रक्रिया है तथा समय समय पर विद्युत् कार्यक्रमो की समीक्षा की जाती है तथा इन्हे आगे बढाया जाता है । विशिष्ट समयावधि के लिए इष्टतम विद्युत् कार्यक्रम बनने मे सभी नए स्थलो का ध्यान रखना पडता है । कहलगाव मे एक वृहत् ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित करने की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए और अन्वेषण करने आवश्यक है । इन अतिरिक्त अन्वेषणो के पूरा हो जाने और इस परियोजना की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित हो जाने के बाद ही एक उपयुक्त समयावधि के विद्युत् कार्यक्रम म कहलगाव परियोजना को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है ।

Abolition of Licence Fee for low cost Radios and Transistors

225 SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR

SHRI K A RAJAN:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state·

(a) whether it is a fact that Government are considering about the abolition of Licence fee of Rs. 7.50 per year on low cost radios and transistors and

(b) if so, what steps Government have taken in this direction so far?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) (a) and (b) The question of licence fee on radio receivers, including low-cost sets, is under consideration.

खानो के राष्ट्रीयकरण के बाद श्रमिकों की मंजूरी में वृद्धि

226. श्री राम नरेश कुशवाहा . क्या ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कोयला खानो के राष्ट्रीयकरण से पूर्व श्रमिको की मजूरी कितनी थी और अब कितनी है, और

(ख) इन मे किन तारीखों म वृद्धि की गई और कितनी वृद्धि हुई ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). कोयला उद्योग मे समय समय मजदूरो की न्यूनतम मजूरी (अन्य लाभो को छोड कर) का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

प्रभावी तारीख	न्यूनतम मजूदरी प्रतिमाह
	रु0
15–8–1967	163
31–12–1974	314
1–1–1975	424

मजदूरो के साथ अभी हाल में किए गए एक अतरिम समझौते के अनुसार एक मजदूर की न्यूनतम मजूरी 1–1–1979 से रु0 512 प्रति माह होगी । इस के अलावा 1-1-1979 के पहले भूमि के नीचे काम करने वाले मजदूरो को 10 प्रतिशत भूमिगत कार्य भत्ता मिलता था । दिनाक 1–1–1979 से यह भत्ता बढा कर मूल मजदूरी का 15 प्रतिशत कर दिया गया है ।

Implementation of Drugs Price Control Order, 1979

227. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Drug industry has not been ready to implement the Drugs Price Control Order, 1979 so far despite repeated warnings by Government; and

(b) if so, the details and what action is proposed to be taken against them?